

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



जनजातीय महिलाओं की आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में सहभागिता (बस्तर विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)

मंजरी मिश्रा, शोधार्थी, समाज कार्य
रीना तिवारी, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग
डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Corresponding Authors

मंजरी मिश्रा, शोधार्थी, समाज कार्य
रीना तिवारी, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग
डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर,
छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 21/01/2021

Revised on : -----

Accepted on : 28/01/2021

Plagiarism : 01% on 21/01/2021



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 1%

Date: Thursday, January 21, 2021

Statistics: 14 words Plagiarized / 1251 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Tkutkrh; efgykvsd dh vkfFkZd, ao "kSf(kd {ks= esa lghHkkbrk ¼cLrj fodkl [k.M ds fo"ks" LkUnHkZ esa ½ Lakfjkrkad fdh Hkh ns"k ds fodkl ds fy, ifjokj fodflr ;kuh f'kfjkr ,ao le>nkj gksuk pkfg. A ifjokj dh mUufr rHkh lEHko gS te ml ifjokj dh efgyk tkozr ,ao xq.korh gks D;ksafd L=h og /kqjh gS fti ij ifjokj fVdk gksrk gSA lekt dh lajpuk esa ukjh dh Hkwfedk u dsoy cPpksa ds fodkl ds fy, mRRkjnk;h gS] cYd og oS;fDr] lkekftd] vkfFkZd jktuhfrd] HkkSxksfyd vkSj lqj{kkRed n"pVdks.kksa ls Hkh vR;Ur egRoiv.kZ gSaA vkt thou dk ,silk dksbZ {ks= ugha gS tgk; efgyk; mRd"V Hkwfedk ugha fuHkkjgh gSaA .d vksj

शोध सार

किसी भी देश के विकास के लिए परिवार विकसित यानि शिक्षित एवं समझदार होना चाहिए। परिवार की उन्नति तभी सम्भव है, जब उस परिवार की महिला जाग्रत एवं गुणवती हो क्योंकि स्त्री वह धुरी है, जिस पर परिवार टिका होता है। समाज की संरचना में नारी की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है, बल्कि वह वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, भौगोलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोणों से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएँ उत्कृष्ट भूमिका नहीं निभा रही हैं। एक ओर जहाँ शहरी महिलाएँ स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर देश के विकास में संलग्न हैं, वहीं दूसरी ओर जनजातिय समुदाय की महिलाएँ खेतों, खलियानों तथा अन्य विविध क्षेत्रों में रात-दिन काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। परंतु ऐसी अनेक जनजातीय महिलाएँ हैं जो अभी तक अपने अस्तित्व एवं अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, एवं पिछड़ापन, पुरानी रूढ़िवादिता एवं अराजकता यदि कम हुए भी है तो कितना, ये समझना होगा। प्रस्तुत अध्ययन जनजातिय बहुल क्षेत्र बस्तर विकास खण्ड के अर्न्तगत जनजातिय महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं शैक्षिक क्षेत्र में सहभागिता, आर्थिक योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता पर केन्द्रित है। प्रस्तुत शोध द्वितीयक तथ्यों एवं वर्णनात्मक प्रकृति पर आधारित है।

मुख्य शब्द

जनजातिय महिलाये, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक स्थिति।

January to March 2021 www.shodhsamagam.com

A Double-blind, Peer-reviewed, Quarterly, Multidisciplinary and Multilingual Research Journal

Impact Factor
SJIF (2020): 5.56

1354

प्रस्तावना

हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है, जिससे उनकी जिन्दगी अभावग्रस्त रही है। इनका खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगो से न के बराबर ही संपर्क रहा है। जनजातियों को हिन्दू समाज में परम्परागत रूप से निम्न समझा गया है और उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, गरीबी आदि का शोषण किया गया है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। शिक्षा व मनोरंजन के केन्द्र, युवागृहों का पतन, यौन रोगों का पनपना, ऋणग्रस्तता, गरीबी, भूखमरी, आवास, बाल विवाह, कन्या मूल्य, संचार, धार्मिक, स्वास्थ्य, भाषा एवं उचित चिकित्सा के अभाव से सम्बन्धित समस्याएँ इनके पिछड़ेपन का कारण है। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या करीब 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत। वहीं जनजातीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में भी काफी परिवर्तन आया है। पूर्व में जनजातीय महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, बालविवाह का प्रचलन, एवं अंधविश्वास, समाजिक कुरीतियों की जड़ें काफी मजबूत थी, परन्तु इस विचारधारा में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता, प्रजनन, बाल और शिशु मृत्यु दर, परिवार नियोजन में अमल, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण, तथा स्वास्थ्य सेवाएँ शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से जनजातीय महिलाओं की आर्थिक समस्याओं का समाधान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति हुई है। वर्तमान में जनजातीय महिलाओं के सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को समझना तथा उनका विश्लेषण करना नितान्त आवश्यक है। जनजातियों के आर्थिक स्रोत सीमित रहें हैं, परिणाम स्वरूप उनमें सुधार ना होने की स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति में निरन्तर परिवर्तन हुआ है। इनके विकास के लिए आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भारत में जनजातीय के समस्त भेदभाव को वैधानिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है और उन्हें अन्य मनुष्यों की भाँति अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनजातियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने तथा अपनी समाजिक-आर्थिक स्थिति ऊँचा करने के लिए संविधान में अनेक धाराएँ सम्मिलित की गई हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातिय महिलाओं की शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ भी प्रदान की हैं। प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में स्थित बस्तर विकास खण्ड के अर्न्तगत निवासरत जनजातिय महिलाओं की आर्थिक एवं शैक्षणिक सहभागिता में प्रकाश डाला गया है। यहां गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा एवं धुरुवा जनजातियां प्रमुख रूप निवास करती है। ग्रामीण निवास स्थान होने पर किसी न किसी रूप से कृषि से जुडी हुई है, एवं जनजातीय समुदाय की महिलाएं भी आर्थिक रूप से उत्पादन, बाजार बिक्री-खरीदी, एवं वनोपज संग्रहण से अपनी जीविका निर्वाह कर रहीं है, साथ ही दुर्गम एवं दूरस्थ स्थान में निवास करने के कारण आवगमन में असुविधा और संचार साधनों का अभाव होने की वजह से मुख्यधारा से संपर्क बना पाने में असमर्थ है। वहीं, अशिक्षा जनजातिय महिलाओं के विकास में एक प्रमुख बाधा ज्ञात हुई है, शिक्षकों एवं सुविधाओं में कमी, आवश्यक भौतिक संसाधनों की कमी, स्कूल भवनों का अभाव, बेरोजगारी तथा अपनी आजीविका के साधनों से वंचित होने के कारण गरीबी, भूखमरी की समस्या एवं भारी ब्याज लेने पर मजबूर है। बस्तर विकास खण्ड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 153,949 जिसमें पुरुष जनसंख्या कुल 76455 तथा महिला जनसंख्या कुल 77494 है। वहीं जनजातियों की कुल जनसंख्या 101517 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या कुल 51370 एवं महिला जनसंख्या कुल 50147 है। इस विकास खण्ड में जनजातिय समुदाय की शैक्षणिक जनसंख्या कुल 66499 है, वहीं पुरुष साक्षरता दर 77.75 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 51.69 प्रतिशत है। इस अनुपात को देखकर यह समझा जा सकता है कि बस्तर विकासखण्ड में जनजातिय महिलाओं का शैक्षणिक स्तर पर सहभागिता पुरुषों की अपेक्षा कम रही है। उनके साथ संपर्क स्थापित करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि उनमें शिक्षा का अभाव है। वह शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने से नहीं वरन् समाज एवं संस्कृति से अनुकूलन स्थापित करने से मानते है। वे अनेक अन्धविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। इनके पिछड़ेपन का कारण भूमि अलगाव, आर्थिक शोषण, ऋणग्रस्तता, बन्धुआ मजदूरी, वनों के नए कानून, जनजातीय जीवन स्तर, सामाजिक

सांस्कृतिक सामजस्य, शासकीय योजनाओं से वंचित, नक्सल प्रभावित निवास स्थान, यातायात साधनों का अभाव आदि है। वास्तव में जनजातिय महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं तो क्रियान्वयन की ओर कदम बढ़ना आवश्यक है। वर्तमान में शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिये सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाएं खोलीं जाये, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हों। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना नहीं करना पड़े। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर विकास खण्ड में जनजातिय महिला के उत्थान के लिए स्कूल चलो अभियान जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा तथा योजनाओं का निर्माण किया गया है। शिक्षा नीति के तहत इनकी स्थिति में सुधार एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु कुटीर उद्योगों व स्व-सहायता समूह, नरवा-गरुवा-घुरुवा-बाड़ी अभियान का निर्माण कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वह आत्मनिर्भर होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आए। यह अध्ययन मुख्य रूप से जनजातीय महिलाओं की आर्थिक एवं शैक्षणिक सहभागिता का विश्लेषण करता है कि वह आर्थिक रूप से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान सम्भव कर सके और इनकी स्थिति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आये।

निष्कर्ष

वर्तमान में जनजातीय महिलाएं और लड़कियां रोजगार की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर रही हैं। वह शहर की जीवन शैली और पर्यावरण के लिए नए हैं और बदलती हुई स्थिति और पर्यावरण के साथ समायोजन करना मुश्किल है। उन्हें स्थानीय भाषा में संचार की कठिनाई एवं आवासीय आवास, रोजगार एवं स्थानीय संपर्क आदि का शहरी जीवन और पर्यावरण के साथ समायोजन करने की समस्या आयेंगी। इन समस्याओं को दूर करने एवं मुख्यधारा से जुड़े रहने के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक होकर लिंग-भेदभाव, शिक्षा में असमानता, तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सर्वांगीण विकास कर सकती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. आहूजा, राम. (2004), *भारतीय समाज*, राव पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बासु, एस. के. (1993), *हेल्थ स्टेट्स ऑफ ट्राईबल वूमन इन इंडिया ऐजुकेशन इम्प्लीकेशन सोशल चेंज*।
3. गिरीयोसन, डब्लू वी. (2008), *मध्यप्रान्त और बरार में आदिवासी समस्याएं*, जनवरी 2008, पृष्ठ 575।
4. हसनैन, नदीम, (2000), *जनजातीय भारत*, जवाहर पब्लिशर्स, दिल्ली।
5. महाजन महाजन, (2004), *जनजातीय समाज का समाजशास्त्र*, विवेश प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. नायडू, पी. आर. (2002), *आदिवासी विकास*, राधा पब्लिकेशंस दिल्ली।
7. राजपूत, उदयसिंह, *आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन*, रावत पब्लिकेशन।
9. मुखोपाध्याय, केलकटा. (1964), *ट्राएबल इकानामी इन सेंट्रल इंडिया*।
10. विद्यार्थी, एल. पी. (2008), *छ.ग. की आदिम जनजातियाँ भाग - 4*।
